



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 वैशाख 1939 (श0)  
(सं0 पटना 394) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

---

सं0 08/आरोप-01-306/2014,सां0प्र0-603

सामान्य प्रशासन विभाग

---

संकल्प

18 जनवरी 2017

श्री सदनलाल जमादार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-299/11 के विरुद्ध अंचलाधिकारी, सिकटी, अररिया के पद पर पदस्थापन काल से संबंधित सरकारी राशि 266715.66/- (दो लाख छियासठ हजार सात सौ पन्द्रह रुपये एवं छियासठ पैसे) के गबन का आरोप जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-510, दिनांक 05.03.1993 द्वारा प्रतिवेदित हुआ। सरकारी राशि के गबन के इस मामले में सिकटी थाना कांड-72/92, दिनांक 27.09.1992 भी दर्ज हुआ, जिसमें इन्हें प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। मामले की गम्भीरता के मद्देनजर विधि विभाग के आदेश सं०-129, दिनांक 11.12.2013 द्वारा श्री जमादार के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी। इसके पश्चात् विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' पुनर्गठित किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के आलोक में आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-17376, दिनांक 17.12.2014 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री जमादार के दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3073, दिनांक 29.02.2016 द्वारा दिनांक 01.02.2016 के प्रभाव से उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ से उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप सं०-01 को अंशतः प्रमाणित एवं आरोप सं०-02 के बारे में मंतव्य दिया जाना आवश्यक नहीं बताया गया। विभागीय पत्रांक-3881, दिनांक 14.03.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए

प्रमाणित आरोपों पर श्री जमादार से बचाव वयान/लिखित अभिकथन माँगा गया जिसके अनुपालन में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण (दिनांक 27.04.2016) समर्पित किया।

3. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री जमादार से प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षा की गयी। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप पर आरोपित पदाधिकारी ने अपने लिखित अभिकथन में स्पष्ट किया है कि राशि का गबन नाजीर द्वारा किया गया था ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित बताया जाना तथ्य परक नहीं है। तथापि श्री जमादार का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अंचलाधिकारी के रूप में यदि उनके द्वारा रोकड़ पंजी की दैनिकी एवं सप्ताहिक जाँच की जाती तो इतनी बड़ी राशि का गबन नहीं होता। इस प्रकार उनके कृत्य एवं लापरवाही से राजस्व की क्षति हुई।

4. उपर्युक्त के आधार पर श्री सदनलाल जमादार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-299/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती (10 वर्षों तक) विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-13427, दिनांक 30.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दी गयी सहमति से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2747, दिनांक 21.12.2016 प्राप्त हुआ।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत श्री सदनलाल जमादार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-299/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती (10 वर्षों तक)।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>